(iii) Inclusion of iron and steel in the list of high priority industry for purposes of foreign investment;

(iv) De-rcgulation of pricing and distribution of iron and steel;

(v) Reduction of duty on import of capital goods; and

(vi) Liberalisation of import and export policy.

With higher economic growth and increased production of steel, steel consumption is also expected to increase.

Removal of gender discrimination from society

1908. SHRI RAJUBHAI A. PARMAR: SHRI SUSHILKUMAR SAMBHAJIRAO SHINDE: SHRIMATI VEENA VERMA:

Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government have evolved any comprehensive scheme for removing gender discrimination from Indian Society by way of female literacy, promoting mother and child health programme and the like;

(b) if so, the details of such a scheme, phase-wise; and

(c) the provision made or being made therefor under the 8th Five Year Plan?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT) (KUMARI VIMLA VERMA): (a) and (b) Government have been implementing a number of schemes of affirmative action with the objective of raising the social, econonic, educational, health and nutritional status of women and attempting to increase awareness of this phenomenon.

(c) The Planning Commission has allocated a sum of Rs. 225.85 crores during the 8th. Plan for women specific programmes of the Department of Women & Child Development.

आयल-पाम की खेती को लोकप्रिय बनाना

1909. **श्री संघ प्रिय गौतम** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि**:**

(क)क्या राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड देश के विभिन्न भागों में आयात-पाम की खेती को लोकप्रिय बनाने के लिए प्रयास कर रहा हैं;

(ख)यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में, विशेषकर उत्तर प्रदेश में इस संबंध में किए गए कार्य का ब्यौरा क्या हैं; और

(ग)क्या देश को निकट, भविष्य में खाद्य तेल के क्षेत्र में आत्म-निर्भरता प्राप्त हो जाएगी?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्ममद अयूब खन) : (क) और (ख) राष्ट्रीय डेरी विकासण बोर्ड को आयल-पाम विकास कार्यक्रम शुरू करने के लिए केवल कर्नाटक राज्य में ही क्षेत्र आवंटित किया गया। एन डी डी बी ने कर्नाटक में माण्डया के नजदीक एक नर्सरी शुरू की थी और आयल-पाम पौध रोपण के अंतर्गत 12 हैक्टेयर क्षेत्र को कवर किया था। तथापि, हाल ही में कर्नाटक सरकार ने सूचित किया हैं कि एन डी डी बी कार्यक्रम में भाग लेने का इच्छुक नहीं हैं।

उत्तर प्रदेश में आयल पाम विकास के लिए कोई कार्यक्रम नहीं हैं क्योंकि आयल पाम की खेती के लिए कृषि जलवायु की परिस्थितियां उपयुक्त नहीं हैं।

(ग)योजना आयोग ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक तिलहनों तथा खाद्य तेलों की मांग को ध्यान में रखतेए हुए 23 मिलियन मीटरी टन तिलहन का लक्ष्य निर्धारित किया हैं और यह संभावना हैं कि हम 1996-97 तक 23 मिलियन मीटरी टन. के उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। इस प्रकार हम तिलहनों तथा खाद्य तेलों मे आत्म-निर्भरता प्राप्त करने की राह में हैं।